राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर विभिन्न वर्गों को मिलेंगी सौगातें

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार भी मौजूद थे।

- युवा, किसान एवं महिला कल्याण हमारी प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा
- आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में दिए दिशा-निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के जरिये युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित विभिन्न वर्गों को विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं योजनाओं का शुभारम्भ कर विशेष सौगातें दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियां समय से पूरा कर ली जाए।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों की निरंतर समीक्षा करें, जिससे यह आयोजन सफल बन सके।

मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के युवाओं को 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रोजगार उत्सव के जरिये नियुक्ति एवं भर्तियों की सौगात दी जाएगी, इसके लिए संबंधित विभाग पूर्व में ही सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें। उन्होंने 'रन फॉर विकसित राजस्थान' के आयोजन में युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक एवं पशुपालकों को दी जाने वाली विभिन्न सौगातों की समीक्षा की। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस आयोजन में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें।

शर्मा ने निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली विकास प्रदर्शनियों में राज्य सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी आकर्षक तरीके से प्रदर्शित की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनकी जानकारी प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान होने वाले विभिन्न लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यों की भी समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

उपचुनाव की सात विधानसभा सीटों का परिणाम आज

- जिला मुख्यालयों झुंझुनूं, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और डूंगरपुर पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी

जयपुर। राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को हुए उपचुनावों के रिजल्ट शनिवार को आएंगे। प्रदेश के 7 जिला मुख्यालयों झुंझुनूं, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और डूंगरपुर पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलट गिने जाएंगे। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। पांच सीटों पर विधायकों के सांसद बनने और दो पर विधायकों के निधन की वजह से उपचुनाव हुए हैं। इन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें भाजपा के पास सलूंबर को छोड़कर कोई सीट नहीं थी।

दौसा सीट से कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा, देवली-उनियारा से हरीश मीना, झुंझुनूं से बृजेंद्र सिंह ओला, खींवसर से हनुमान बेनीवाल, और चौरासी विधानसभा सीट से विधायक राजकुमार रोत के सांसद बन जाने से सीटें खाली हुई थी। सलूंबर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन होने की वजह से सीट खाली हुई है।

ईवीएम से वोटों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू की जाएगी। इसके लिए, 98 टेबल लगाई गई है। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 141 राउंड में ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। वोटर्स की संख्या के आधार पर 18 से 22 राउंड में गिनती होगी। 13 नवंबर 2024 को हुए मतदान में 7 सीटों पर औसतन कुल 69.72 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।

वहीं, 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में 74.74 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। सात सीटों में से 6 सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कम वोटिंग हुई थी। इन सात में सबसे ज्यादा 75 प्रतिशत से ज्यादा मतदान खींवसर और रामगढ़ सीट पर हुआ था।

वहीं, खींवसर सीट पर उपचुनाव में विधानसभा चुनाव 2023 से 2.13 फीसदी ज्यादा वोटिंग हुई थी। खींवसर सीट पर 2023 के मतदान प्रतिशत 73.49 की तुलना में अब उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़कर 75.8 हो गया। दौसा सीट पर पिछली बार से 12.10 प्रतिशत कम वोट वोटिंग हुई थी।

झुंझुनूं बी.डी.के. अस्पताल के पी.एम.ओ. सहित तीन चिकित्सक निलम्बित

जयपुर। झुंझुनूं के राजकीय बीडीके अस्पताल की आपातकालीन इकाई में एक जीवित युवक को मृत घोषित करने के प्रकरण को स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही मानते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। प्रकरण में झुंझुनूं कलक्टर द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर विभाग ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप पचार, डॉ. योगेश कुमार जाखड़ एवं डॉ. नवनीत मील को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही मामले की विस्तृत जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गयी है।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए संयुक्त निदेशक जयपुर जोन डॉ. नरोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी में कांवटिया अस्पताल में मेडिकल जूरिस्ट डॉ. अजय श्रीवास्तव, डॉ. हिम्मत सिंह राठौड़ एवं डॉ. धीरज वर्मा को शामिल किया गया है। कमेटी को 7 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

निलम्बन अवधि में डॉ. संदीप का मुख्यालय सीएमएचओ कार्यालय जैसलमेर, डॉ. योगेश का सीएमएचओ बाड़मेर एवं डॉ. नवनीत मील का सीएमएचओ जालोर कार्यालय किया गया है।

अडानी की गिरफ्तारी की मांग

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सेबी के अमेरिकी समकक्ष, प्रतिभूति विनिमय आयोग का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके सात सहयोगियों ने भारत में उच्च-भुगतान वाले सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2,000 करोड़ (250 मिलियन) की रिश्वतखोरी की योजना बनाई। ऐसे में इस मामले की जांच कर मामले की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। डोटासरा ने कहा कि अडानी पर आरोप लगने पर भाजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना संदेह के घेरे में आता है। उन्होंने अडानी की गिरफ्तारी करने की मांग की है। डोटासरा ने कहा कि अमेरिकी अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2020 और 2024 के बीच, अडानी और उनके सह-प्रतिवादियों ने 16,000 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की।

ई.आर.सी.पी. का शिलान्यास भी हम करेंगे और लोकार्पण भी हम करेंगे : सुरेश रावत

- 'कांग्रेसी बयानवीर झूठे बयानों से जनता को गुमराह नहीं करें'
- 'पूर्ववर्ती सरकार ने ईआरसीपी पर जनता को गुमराह किया जिसका नतीजा सबके सामने है'
- 'हमारी सरकार परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 10 हजार करोड़ के कार्यों के शीघ्र शिलान्यास करेगी'

जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष के ईआरसीपी पर दिये गये बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी बयानवीर ईआरसीपी पर अपने झूठे बयानों से जनता को गुमराह नहीं करें। भजनलाल सरकार ईआरसीपी के सपने को साकार करने का कार्य कर रही है और जल्द ही शिलान्यास होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हमारी सरकार द्वारा 10 हजार करोड़ के कार्यों को शीघ्र आरम्भ कराये जाने हेतु शिलान्यास कराया जाएगा।

रावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रीय परियोजना में स्वीकृति किये जाने का सन्दर्भ देकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे है। ईआरसीपी योजना (पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना-एकीकृत ईआरसीपी) को भारत सरकार द्वारा नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया है। भारत सरकार की नदी जोड़ो परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। इसके अन्तर्गत सिंचाई, पेयजल लाभों को शामिल करते हुए इसे वृहद् रूप दिया है।

जल संसाधन मंत्री रावत ने कहा कि कांग्रेसी ईआरसीपी परियोजना पर बयान देने से पहले अपनी गिरेबां में झांक लेते कि नवनेरा-बैराज-ईसरदा बांध का कार्य हमारी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा आरम्भ कर दिया गया था परन्तु पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इनकी मंशा इसे आगे बढ़ाने की नहीं थी। अब हम इन कार्यादेश को शीघ्र ही पूरा कराने जा रहे है।

नेता प्रतिपक्ष झूठे आंकड़ो से खेलना बंद करें। ईआरसीपी के लिए इनकी सरकार के समय 10 हजार करोड़ रूपए देने के कागजात जनता के सामने रखे ताकि जनता को इनकी कथनी और करनी में अंतर पता चल सके। क्योंकि होटलों में समय बिताने वाले इन बयानवीरों ने अपने बयानों से ही राजस्थान का विकास किया था। जिसको जनता ने धूल चटा दी और आज कांग्रेस उपचुनाव में भी इन झूठे बयानवीरों के कारण चुनाव हार रही है।

'ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाय'

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की है कि वे पार्वती-काली सिंध-चंबल एवं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (पीकेसी-ईआरसीपी प्रोजेक्ट) को नदी जल राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। इसके साथ ही राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के बीच हुए एमओयू को राज्य हित में सार्वजनिक किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आगामी 15 दिसंबर को इस बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास करने राजस्थान आ रहे हैं। इस मौके पर उन्हें इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। इस बारे में मोदी ने अजमेर में एक जनसभा में राज्य की जनता से वादा भी किया था। प्रधानमंत्री को अब अपना यह वादा निभाना चाहिए।

शास्त्रीय विधाओं की प्रस्तुति के साथ 100वां तानसेन समारोह शुरू

जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित तानसेन समारोह में तबला वादकों ने अपनी प्रस्तुति देकर श्रोताओं का मन मोह लिया।

जयपुर। वायलिन की मधुर धुन, तबला वादन और गायन प्रस्तुति में शास्त्रीय राग-रागिनियों की गूंज। जवाहर कला केन्द्र में शुक्रवार को शास्त्रीय विधाओं की सम्मिलित प्रस्तुतियां हुई। मौका रहा मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और जवाहर कला केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 100वें तानसेन समारोह का। "तानसेन शताब्दी समारोह" के अंतर्गत राष्ट्रीय "आगाज" श्रृंखला की शुरुआत जयपुर से हुई। विभिन्न शहरों में भी समारोह का आयोजन किया जाएगा।

रंगायन में दोपहर को तानसेन केंद्रित संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने विचार रखा। चर्चा में वरिष्ठ ध्रुवपद गायिका प्रो. डॉ. मधु भट्ट तैलंग, वरिष्ठ कला समीक्षक और संस्कृतिकर्मी डॉ. राजेश कुमार व्यास और प्रख्यात सुरबहार वादक डॉ. अश्विन दलवी ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने संगीत सम्राट तानसेन की जीवनी, शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला। डॉ. मधु भट्ट तैलंग ने बताया कि ध्रुवपद गायिकी तानसेन की देन है, तानसेन महान कलाकार थे जिनकी महत्ता को सभी धर्मों और हर काल में स्वीकार किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि शास्त्रीय गायन में विभिन्न वाणियों के जनक भी तानसेन ही रहे। डॉ. राजेश कुमार व्यास ने कहा कि आधुनिक भारतीय संगीत की कल्पना तानसेन की बिना नहीं की जा सकती, उन्होंने ध्रुवपद को परिष्कृत कर जन जन तक पहुंचाया। डॉ. अश्विन दलवी ने एक किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि जब अकबर ने तानसेन से पूछ कि आपसे श्रेष्ठ कौन है तो उन्होंने अपने गुरु हरिदास जी के बारे में बताया। यह बात न केवल गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताती है बल्कि कलाकार का व्यवहार किस तरह सरल और सहज होना चाहिए इस बात पर जोर देती है। शाम को शास्त्रीय संगीत की महफिल सजी जिसमें वायलिन वादन, तबला वादन और शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति हुई। पं. प्रवीण शेवलिकर एवं चेताली शेवलिकर ने वायलिन वादन किया। राग यमन के साथ उन्होंने प्रस्तुति की शुरुआत की और विभिन्न राग प्रस्तुत की। रामेन्द्र सिंह सोलंकी ने तबले पर संगत की। इसके बाद प्रो. प्रवीण उद्धव व श्रुतिशील उद्धव ने अपना परंपरागत स्वतंत्र तबला वादन सर्वलोक प्रिय ताल 'तीन ताल' में प्रस्तुत किया। जिसमें विलंबित लय में आलापचारी सदृश्य पेशकार दिल्ली, फर्रुखाबाद और पंजाब की खुशबू के साथ मुक्त रूप से विस्तारित करते हुए अजराड़ा, बनारस और लखनऊ घरानों के विशिष्ट कायदें, बांट, रत कायदे आदि के साथ कायदे के विविध प्रकार प्रस्तुत किये। प्रो प्रवीण उद्धव व श्रुतिशील उद्धव जी ने अपने स्वतंत्र वादन के प्रस्तुतीकरण की एक अलग शैली विकसित की है। आपके वादन में मंद्र और तार दो सप्तक के तबले की नादात्मकता का आनंद श्रोताओं को प्राप्त हुआ। अपने परंपरागत वादन पद्धति के साथ-साथ आधुनिक वादन भी प्रस्तुत किया। इनके वादन में नाद विविधता, भाषा सौंदर्य, साहित्य, काव्यात्मकता, जाति, छंद आधारित अनेक रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया तत्पश्चात मध्य लय में पंजाब घराने और बनारस की छंदाधारित गत, लमछड़ चक्रदार बंदिशे, अलग-अलग जातियों के रेलें आदि प्रस्तुत किया। संपूर्ण तबला वादन में सभी घराने के बंदिशों के साथ-साथ घराने के मूर्धन्य विद्वान पंडित किशन महाराज, उस्ताद अल्ला रखा खां साहब, पंडित सुरेश तलवलकर, उस्ताद जमाल खां, उस्ताद अफाक हुसैन खान साहब, पंडित अनोखेलाल, पंडित सामता प्रसाद आदि अनेक विद्वानों की रचनाओं को प्रस्तुत कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पं. धर्मनाथ मिश्र ने हारमोनियम पर संगत की।

यू.टी.बी कार्मिकों का भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन

जयपुर। यूटीबी कार्मिक एक बार फिर सरकार और प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए है। शुक्रवार को यूटीबी कार्मिकों ने बड़ी संख्या में प्रदेश भाजपा कार्यालय और स्वास्थ्य भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। यूटीबी कार्मिक सुबह 11 बजे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और करीब चार घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद यूटीबी कार्मिकों को भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने वार्ता के लिए बुलाया और यूटीबी कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान यूटीबी कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

भर्तियों में मुद्दों के निस्तारण के लिए क्यों ना एस.ओ.पी. व विभागीय कमेटी बने : हाईकोर्ट

- 'हर सरकारी विभाग में शिकायत निवारण कमेटियां बनाई जाए जो अभ्यर्थियों की शिकायतों का शुरुआती स्तर पर ही निस्तारण कर सकें'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में विभिन्न मुद्दों के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने और इसमें देरी होने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से कहा है कि क्यों ना अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए एक एसओपी तैयार की जाए। वहीं हर सरकारी विभाग में शिकायत निवारण कमेटियां बनाई जाए जो अभ्यर्थियों की शिकायतों का शुरुआती स्तर पर ही निस्तारण कर सकें। इसके साथ ही अदालत ने राज्य के एजी बसंत सिंह छाबा व विज्ञान शाह से कहा है कि वे इस संबंध में कार्मिक विभाग से भी चर्चा करें और भर्तियों के संबंध में सभी सरकारी विभागों से प्रपोजल मांगें। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश एएनएम भर्ती में विभिन्न मुद्दों पर दायर ज्योति कुमारी मीना व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालती आदेश के पालना में प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ और प्रमुख विधि सचिव ब्रजेन्द्र कुमार जैन अदालत में उपस्थित हुए। मेडिकल विभाग की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने कहा कि विभाग की भर्तियों में अस्थाई सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से परिवेदनाएं ली जाती हैं और इन्हें परिवेदना कमेटी के पास भेजा जाता है। इसके बाद इन्हें नीति निर्धारण समिति में रखा जाता है। वहीं विधि विभाग की ओर से कहा गया कि एडीजे भर्ती में भी आपत्तियों का निस्तारण किया और राज्य सरकार के विभागों से चर्चा कर एसओपी बनाई जा सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरपीएससी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अखबारों की खबरों से पता चल रहा है कि आरपीएससी में चयन कैसे हो रहे हैं। वहां पर पारदर्शिता की कमी है और भेदभाव होता है। कई बार जिन अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में कम अंक होते हैं उनके साक्षात्कार में ज्यादा अंक दे दिए जाते हैं। वहीं अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर मामले की सुनवाई 28 नवंबर को तय की है।

ज्यादा से ज्यादा कृषकों को दिया जाये प्रशिक्षण : राजन विशाल

शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने शुक्रवार को दुर्गापुरा स्थित इन्टरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर का दौरा किया।

जयपुर। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने शुक्रवार को दुर्गापुरा स्थित इन्टरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर का दौरा कर अधिकारियों को ट्रेनिंग सेन्टर में ज्यादा से ज्यादा कृषकों को उन्नत तकनीकी का कृषि प्रशिक्षण देने के लिए कहा।

राजन विशाल ने कृषकों को प्रशिक्षण के दौरान प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु संस्थान के फल वृक्ष क्षेत्र, संरक्षित खेती, सब्जी उत्पादन, नर्सरी, ड्रिप इरिगेशन आदि गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने आईएचआईटीसी के कैम्पस, छात्रावास, प्रयोगशाला आदि सभी जगहों का बारीकी से निरीक्षण किया और संस्थान की साफ-सफाई एवं मेन्टिनेन्स के आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।

शासन सचिव ने अधिकारियों को प्रशिक्षण में कृषकों की संख्या को बढ़ाने व पूरा ट्रेनिंग प्लान तैयार रखने के लिए निर्देशित किया। साथ ही संस्थान में हाइड्रोपोनिक्स की स्थापना के लिए भी कहा। हाइड्रोपोनिक प्रणाली मिट्टी के बजाय पानी आधारित पोषक घोल का उपयोग करके पौधे उगाने की तकनीक है। हाइड्रोपोनिक उत्पादन प्रणाली का प्रयोग छोटे किसानों और वाणिज्यिक उद्यमों द्वारा किया जाता है।

इसके बाद शासन सचिव ने श्री कर्ण नरेन्द्र विश्वविद्यालय के संगठन संस्थान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में स्थित समन्वित कृषि प्रणाली प्रक्षेत्र का दौरा किया। यह समन्वित कृषि प्रणाली इकाई डेढ़ हैक्टेयर कृषि जोत हेतु राजस्थान के सिंचित क्षेत्र के किसानों की पोषण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। इस समन्वित कृषि प्रणाली क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसल पद्धतियां, उद्यानिकी फल एवं सब्जियां, डेयरी यूनिट, बकरी यूनिट, पोल्ट्री यूनिट, अजोला यूनिट, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट और गोबर खाद यूनिट है।

समन्वित कृषि प्रणाली के मुख्य शष्य वैज्ञानिक डॉ. उम्मेद सिंह ने किसानों के लिए सालभर आय का अच्छा स्त्रोत होने एवं किसान के परिवार के लिए पोषण युक्त भोजन जैसे फल, सब्जी, अनाज, दाल, मोटे अनाज, तिलहन, पशुओं के लिए चारा एवं इससे जनित अपशिष्ट के सदुपयोग हेतु वर्मी कम्पोस्ट, गोबर की खाद इत्यादि के रूप में प्रयोग करने से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार एवं बाहरी उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की जानकारी दी। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बलराज सिंह ने कृषि विश्वविद्यालय एवं दुर्गापुरा में संचालित विभिन्न कृषि अनुसंधान योजनाओं की जानकारी दी।

इस दौरान आयुक्त उद्यानिकी सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त निदेशक कृषि (रसायन), एच.एस. मीना, संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन) अजय कुमार पचौरी, संयुक्त निदेशक उद्यान महेन्द्र कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण) गजानंद यादव, उप निदेशक उद्यान (आईएचआईटीसी) राजेश कुमार गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

ज्योति कलश रथ यात्रा का स्वागत

जयपुर। टीम 39 "जहां चाह वहां राह" जन कल्याण ट्रस्ट पानीपेच द्वारा गायत्री तीर्थ शान्तिकुंज हरिद्वार से देश के 2400 तीर्थों के पवित्र जल-रज के साथ ज्योति कलश रथ का शुक्रवार को सुबह स्वर्णकार सेवा सदन, आर.पी.ए रोड पर टीम 39 द्वारा पुष्प वर्षा करके व आरती द्वारा स्वागत किया गया। टीम 39 के मीडिया प्रभारी मनीष केडिया व प्रधान ट्रस्टी विष्णु बियानी ने बताया कि कार्यक्रम में नेहरू नगर विकास समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ताराचंद खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष संजीव सरोलिया भंवरलाल मीणा मौजूद थे।

राइजिंग राजस्थान से प्रदेश की पूरे देश में उभरेगी नई पहचान : भजनलाल शर्मा

- समिट के सुनियोजित आयोजन एवं ब्रांडिंग के दिए विस्तृत निर्देश
- 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' की तैयारियों की समीक्षा बैठक

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का वृहद् स्तर पर आयोजन करने जा रही है तथा इस समिट के माध्यम से प्रदेश की पूरे देश में एक नई पहचान उभरेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान होने वाली सभी गतिविधियों का सुनियोजित एवं भव्य स्तर पर आयोजन सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह समिट निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही पूरे देश में अपनी छाप छोड़ सके।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि समिट के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए कार्य निर्धारण के साथ अधिकारी नियुक्त किए जाएं और उनकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाए।

शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश देते हुए कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट से लेकर विभिन्न कार्यक्रम स्थलों के रास्तों पर आकर्षक होर्डिंग्स एवं बैनर लगाए जाएं। साथ ही, समिट में कंट्री पार्टनर के तौर पर शामिल होने वाले देशों की जानकारी को भी प्रमुख स्थानों पर विशेष रूप से दर्शाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपने आतिथ्य-सत्कार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि समिट में भाग लेने के लिए आने वाले ब्रांड एम्बेसडर, निवेशकों एवं अन्य अतिथियों को सरल एवं सहज सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। साथ ही, उन्होंने उद्घाटन सत्र के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों, अतिथियों की बैठक व्यवस्था तथा अन्य तैयारियों के विषय में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को तैयारियों को अन्तिम रूप देने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य रोहित गुप्ता, राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।